

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
 पीठाधीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 126/2015

अपील संख्या : 81/2015

अपीलपट

1 मदनकर पति गोरक्षसिंह जाति राजपूत निवासी मारवाड जंक्शन

बनाम

रूपसिंह

1 भवसिंह पुत्र सुलतानसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा 2 भूकसिंह पुत्र हिमलसिंह के का.सू.

2.1 देवीसिंह पुत्र भूकसिंह

2.2 पर्वतसिंह पुत्र भूकसिंह

2.3 मदनसिंह पुत्र भूकसिंह

2.4 गुमानसिंह पुत्र भूकसिंह

2.5 नाहरसिंह पुत्र भूकसिंह

2.6 सावंकर पति भूकसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा

2.7 निहालकर (नेलाकर) पति कृन्दासिंह पुत्री भूकसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा

3 लालसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजसमन्द

4 मंगलसिंह पुत्र साहनसिंह के राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा

4.1 सज्जनकर पति मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा

4.2 श्रवणकर पति नरेन्द्रसिंह पुत्री मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा

4.3 प्रकाशकर पति सुभरसिंह पुत्री मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी कसौली तहसील देसरी

5 शीक कर बंधा कानसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा

6 भवरकर बंधा नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा

7 इन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मांजरा



राजस्थान उच्च न्यायालय  
 जयपुर

१





राजस्थान अधीनस्थ विभाग  
स्त्री

विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम गुडा भोजराज (सामावास) के खसरा नम्बर 51 रकबा 5.5391 हैक्टयर की भूमि में से अधीनस्थ द्वारा रेसोडिन्स से 0.2529 हैक्टयर अर्थात् 1 बीघा भूमि जसि रेजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की तथा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण, जो इस अधीनस्थ संयोजित है, ने मिलावट कर बिना अधीनस्थ को पक्षकार नियोजित किए दिनांक 11.10.2013 को वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कांस्ट्रक्शंस अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी अन्य भूमियां सहित खसरा नम्बर 51 की सम्पूर्ण आराजी खसू की बताते हुए विभाजन का अर्जोप बाहा। दिनांक 11.03.2014 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष सहमति व्यक्त करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन को अधिकृत करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का निवेदन किया, जो तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई। जबकि वाद विचारण से पूर्व ही राजस्व रेकॉर्ड में अधीनस्थ का नाम बतौर सह खतौदार दर्ज था, इसके बावजूद भी न तो अधीनस्थ को पक्षकार बनाया गया तथा न ही उसे किसी प्रकार से खसरा नम्बर का अवसर दिया गया। समस्त कायदाही वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मिलावट कर सम्पादित करवाड़े है, जो आरम्भ से ही बर्न्य है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार बिना खसरा नम्बर का अवसर प्रदान किया, किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ के एक अधिकार, आधिपत्य, कष्ट, निर्माण आदि होते हुए भी उसे जानकारी दिए बिना, उसे खसरा नम्बर का अवसर प्रदान किया बिना खसरा नम्बर का अवसर पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः

अधीनस्थ को इस निर्णय के जसि निर्णय पारित किया जाता है। को इस निर्णय के जसि निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम गुडा भोजराज (सामावास) के खसरा नम्बर 51 रकबा 5.5391 हैक्टयर की भूमि में से अधीनस्थ द्वारा रेसोडिन्स से 0.2529 हैक्टयर अर्थात् 1 बीघा भूमि जसि रेजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की तथा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण, जो इस अधीनस्थ संयोजित है, ने मिलावट कर बिना अधीनस्थ को पक्षकार नियोजित किए दिनांक 11.10.2013 को वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कांस्ट्रक्शंस अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी अन्य भूमियां सहित खसरा नम्बर 51 की सम्पूर्ण आराजी खसू की बताते हुए विभाजन का अर्जोप बाहा। दिनांक 11.03.2014 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष सहमति व्यक्त करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन को अधिकृत करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का निवेदन किया, जो तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई। जबकि वाद विचारण से पूर्व ही राजस्व रेकॉर्ड में अधीनस्थ का नाम बतौर सह खतौदार दर्ज था, इसके बावजूद भी न तो अधीनस्थ को पक्षकार बनाया गया तथा न ही उसे किसी प्रकार से खसरा नम्बर का अवसर दिया गया। समस्त कायदाही वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मिलावट कर सम्पादित करवाड़े है, जो आरम्भ से ही बर्न्य है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार बिना खसरा नम्बर का अवसर प्रदान किया, किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ के एक अधिकार, आधिपत्य, कष्ट, निर्माण आदि होते हुए भी उसे जानकारी दिए बिना, उसे खसरा नम्बर का अवसर प्रदान किया बिना खसरा नम्बर का अवसर पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः

दिनांक: 16.11.17

:- निर्णय :-

1. श्री पीएमओ जोशी, विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ
2. श्री राजेंद्रसिंह राजपुत्री, विद्वान अभिभाषक रेसोडिन्स
3. सरकारी प्रोकर, रेसोडिन्स संख्या 22 की ओर से

उपस्थित :-

अधीनस्थ अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान कांस्ट्रक्शंस अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकरण  
अपील



विद्वान अधिभाषक रेस्पॉन्डेंट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया, उसमें तकनीकी त्रुटि के कारण अधीलापट का नाम पक्षकार बनाने से छूट गया। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्राथमिक डिफेंडेंट की पालना में जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें अधीलापट का हिस्सा दर्शाया गया है। अधीलापट के पक्ष में रेस्पॉन्डेंट्स द्वारा 1 बीघा भूमि का विवरण दर्शाया है, वह भूमि अधीलापट को सड़क पर दी गई है, जो इनके हिस्से में है। अधीलापट ने इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिफेंडेंट के खिलाफ अर्जतार वादा है, जबकि प्रकरण में अन्तिम डिफेंडेंट जो युक्ति है तथा उस अन्तिम डिफेंडेंट के अर्जकम में राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन हो चुका है। उक्त डिफेंडेंट अर्जतार रेस्पॉन्डेंट्स द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ किया, जो अधीलापट ने उक्त निर्माण कार्य रोकवा दिया। जो भूमि रेस्पॉन्डेंट्स द्वारा अधीलापट को विक्रय की है, उसमें अधील प्रस्तुत करने से पूर्व ही वारंटीवारी बनी हुई है। उसमें रेस्पॉन्डेंट्स द्वारा कभी भी इस्तखफ नहीं किया। अधीलापट 1 बीघा भूमि की हकदार होते हुए भी सम्पूर्ण भूमि पर स्वामन आदेश जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अब अधीलापट जिस अर्जतार के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है, वह अर्जतार तो उन्हे पूर्व में ही दिया जा चुका है। अतः अधील खारिज करावे।

उभयपक्ष अधिभाषकमण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। रेस्पॉन्डेंट्स संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कायदेकरी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा धनला के खसरा नम्बर 51, 52, 53, 54, 55, 57, 639, 640, 680, 681, 682, 683 व 756 कुल खसरा 13 जिसका कुल रकबा 39.4815 हेक्टेयर की भूमि वादीमण एवं प्रतिवादीमण के हिस्से अर्जतार अधीन कर शुल्क से राजस्व रेकॉर्ड में इन्दाज करवाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीमण को जारिय सम्मन तलब किया। इसके पश्चात् दिनांक 11.03.2014 को वादीमण एवं प्रतिवादीमण की सहमति के आधार पर प्रकरण में प्राथमिक डिफेंडेंट जो करने के आदेश जारी किया गए तथा प्राथमिक डिफेंडेंट पर वादा जारी करते हुए वादग्रस्त आरजी का दानो पक्षों की उपस्थिति में वाई मिसेस एण्ड बार्डरेड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को आदेश दिये गए। इस आदेश की पालना में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपने पत्राक/राजस्व/43 दिनांक 08.01.2015 के जारिय प्राथमिक डिफेंडेंट की पालना में प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित किया, जिसमें अधीलापट के हिस्से में खसरा नम्बर 51/65 रकबा 0.2529 हेक्टेयर की भूमि रखी गई, जबकि अधीलापट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय वाद में न तो पक्षकार थी तथा न ही अधीलापट को वाद में किसी प्रकार से धारावाही करने का अवसर ही दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितवद्ध पक्षकार को बिना सूचनापूर्वक का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायविरत नहीं है। इस्तगत प्रकरण में अधीलापट को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सूचनापूर्वक का अवसर दिये, उसकी सह खातेदारी भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश पारित किए गए, जो विधि सम्मत नहीं है। इस परिप्रेष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए अधील आदेश को न्यायविरत नहीं माना जा सकता है।

राजस्थान कायदा अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जमीनों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित हैं। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान कायदा अधिनियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत किये जाने के प्रावधान हैं। द्वारा जित का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान हैं। राजस्थान कायदा अधिनियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 में विभाजन के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिये गये हैं, उनके अन्तर्ग में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर ऐसा कोई ठोस कारण दर्शाया नहीं जाता, जिसके आधार पर जैर अपील निर्णय एवं हिकी को अर्जित ठहराया जा सके। लिहाजा अपीलान्ट की अपील सारहीन पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जखान द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2013 शंवरसिंह वगैरा बनाम शंवरकर वगैरा में पारित निर्णय व हिकी दिनांक 11.03.2014 तथा 11.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रिषित किया जाता है कि हितवद्ध पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान कायदा अधिनियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विहित समत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति संबंधित पत्रावलीयां में संलग्न की जावे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकॉर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खूले न्यायालय में सुनाया गया।



(श्री शंवरसिंह चौहान)  
राजस्थान अपील महानिरीक्षण, पृथी

MS